संपादकीय

भारत कृषक समाज अपनी 60वीं वर्षगांठ 25–26 अप्रैल, 2015 को हरिद्वार, उत्तराखंड़ में मना रहा है। 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हम 20 राज्यों से 1,000 से अधिक किसानों के सम्मिलित होने की उम्मीद कर रहे हैं (विवरण के लिऐ पृष्ट 8 देखें)।

आने वाले वर्ष में हम विभिन्न राज्यों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे जिनकी सूचना आपको कृषक समाचार के माध्यम से अवगत करा दी जाऐगी। इस अवसर पर हम एक स्मारिका का भी प्रकाशन कर रहे हैं। हम आप सभी से विभिन्न गतिविधियों के बारे में विचार देने का अनुरोध करते हैं।

समाज के बारे में जानकारी तथा हाल ही में की गई गतिविधियों को आप निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाकर देख सकते हैं;

बी.के.एस. – *www.bks.org.in*

फॉमर्स फोरम – *www.farmersforum.in*

कृषक समाचार – *www.bks.org.in/krishak-samachar/*

गतिविधियों की सूची – *www.bks.org.in/activities/*

जो भी हमारे साथ अपना मोबाईल नंबर तथा ई–मेल पंजीकृत करवाता है हम उनके लिऐ एस.एम.एस. तथा ई–मेल सेवा को भी शुरू करने जा रहे हैं। आप हमें अपनी जानकारी (नाम, पिता का नाम, पता, पिन कोड़ तथा मोबाईल नंबर) इस मोबाईल नं. 09910430613 तथा इस ई–मेल पते *ho@bks.org.in* पर भेज सकते हैं। इससे हमें आपको भविष्य में हमारी गतिविधियों के बारे में सूचित करने में मदद मिलेगी।

पिछले महीने में हमें माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी, प्रधानमंत्री जी के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रमण्यम तथा डॉ० बिबेक देबरॉय, निति आयोग ने विचार विमर्श के लिऐ बुलाया था। हमारे सुझाव कृषक समाचार के पिछले अंक में प्रकाशित किऐ गऐ हैं।

मैं नियमित रूप से समाज की ओर से विभिन्न प्रकाशनों के लिऐ लिखता हूँ तथा हाल ही में प्रकाशित मेरे दो लेखों को इस अंक में छापा जा रहा है। मेरे द्वारा लिखे अन्य लेखों को *www.ajayvirjakhar.com* पर जाकर देखा जा सकता है। सभी सदस्यों से अनुरोध हैं कि वह मेरे लेखों पर अपनी प्रतिक्रिया दें और अगर वह असहमत हैं तो विशेष रूप से मुझे अवगत करवाऐं। हमें हमेशा आपके इनपुट की आवश्यकता है।

हम आप सभी को हरिद्वार आने के लिऐ आमंत्रित करते हैं।

हम तंग आ चुके है

अभी कुछ समय पहले ही मैने बर्लीन में एक विरोध को देखा जो उद्ययोगिक खेती और योजनाबध मुक्त व्यापार समझौता जो कि युरोपियन युनियन और युनाईटिड स्टेट के बीच हुआ। इसका टाईटल था ''हम दुःखी हो चुके है'' जब की व्यापार के मसले योरोप में गूंज रहे है। बहुत से किसान व्यापारिक समझौतो के नतीजो के प्रति अनभीज्ञ है। किसानो की उत्सुकता को सरकार अपने सफलता के साथ पुरा करने की कोशिश में है। सफलता धोखा भी दे सकती है। अगर लम्बे समय के समझौतो को छोटे समझौतो को कुर्बान किया जाये या समस्या को न समझा जाये।

यू.पी.ए. सरकार अपने दस साल के शासन में किसानो को अपने साथ ना जोड़ पाई ओर वो लगातार बढ़ती महगांई को वजह से सता से चली गई। उनकी सोच के उल्ट वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट से पहले खेती के विषय पर बातचीत करने के लिए बजट से पहले एक सभा बुंलाई। भारत कृषक समाज ने एक लघु उद्योगो के लिए एक लम्बी सूची प्रधान की। ऐसे निवेश (खर्च) जो ज्यादा फयादा दे ओर पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से लम्बे समय तक चल सके ओर उनके बुरे प्रभाव भी न हो। इस तरह नई सरकार एक योजनाबध दिशा देगी। जो कि खाद्य प्रदार्थो को एक हद तक महंगाई से बचाये। बिना ज्यादा खर्च बल्कि इसी पैसे का सही इस्तमाल करे।

एक तरह से हमे ऐसे जिलो की तलाश करनी चाहिए जहां मौसम, मिट्टी ओर पानी सही हो वहां हम खपत होने वाले उत्पादो को बढ़ाये हम हर साल 4 जिलो को चुने। अगले पांच सालो के लिए उसमे भोजन से सम्बन्धित सरकार के क्रार्यक्रमो को लागू करे ओर सहायता भी दे। जो सहायता इजराईल, नीदरलैण्ड, जर्मनी ओर बाकी देशो से मिलती है। जिसका सम्बन्ध योजनाबध खेती की सेवाओ के साथ हैं। उसे प्रोत्साहन दे। खेती से सम्बन्धित जहां बहुत सी सेवाऐं खत्म हो चुकी है उसके बुरे प्रभावों को हमने नही समझा। हमे पचंवर्षीय योजनाओं में यह चाहिए कि हर दस गावों के साथ एक खेतीबाड़ी में सनात्तक की सेवायें ली जाए ओर इसके साथ एक सांझा लक्ष्य बनाया जाये। ''स्माल फार्मर ऐगरीकल्चर बिजनस कोन्सिटियम ओर नैशनल डेयरी डवैलपमैंट बोर्ड'' जो कि प्याज, आलू, टमाटर की फसल पैदा करे ओर भण्डारण करे ओर उसका सही योजनाबध वित्तरण करें।

इसके बाद सफेद क्रातिं को पूरे भारत में प्रोत्साहन देना चाहिए। देशी नशलों के दुध की उपज को दुगना करके इसके लिए एक सही योजना ओर (आर्टिफिशनल) कृत्रिम गर्भधारण का ध्यान दिया जाये। हर किसान को अच्छी नशल के पशु ओर घर के नजदीक ही पशु चिकित्सा सेवायें दी जायें। भारत की 10 प्रतिशत रासायनिक खाद्यो ओर पेस्टीसाईडस की जगह ओर आरगैनिक (जैविक) खाद्यो को दी जाये जिसके साथ हानिकारक किटो को खत्म किया जाये ओर बायोपेस्टीसाईडस ओर बायो खादों का इस्तमाल किया जाये। 80 प्रतिशत किसान जिसके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है ओर वो खेतीबाड़ी की

मशीने खरीदने में असमर्थ है। यही कारण है कि यह किसान कर्जदार हो चुके है इसकी जगह किसानो को किराये पर खेती ओजारो की सेवायें प्रधान की जाये।

बागबानी, डेयरी, पोलटरी ओर मछली पालन को अगर इक्कठा कर लिया जाये तो यह न सिर्फ कुपोषण को खत्म करेंगे बल्कि पाचं गुणा ज्यादा और रोजगार पैदा करेंगे। हम पैदावार को पोषण के साथ जोड़ सकते है। बाजरा और चारे पर ज्यादा ध्यान दे सकते है। जैसे मिड डे मिल में प्रोटिन युग सोयाबीन दी जाती है और इसका निर्यात भी किया जा सकता है। हर निर्यात फायदेमंद नही हो सकता जैसे की चावल का क्योंकि यह भूमिगत पानी को नष्ट करता है। क्योकि अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में भोजन पदार्थो के मूल्य कम हो रहे है। इस स्थिति में यह अच्छा होगा कि भारत अपनी सीमाओ को आयात के लिए खोल दे। वाणिज्य मत्रांलय की कही ना कही मर्जी ओर डील के कारण किसानो की आत्महत्याऐं बड़ी है मुझे विश्वास है कि नई प्रशासनिक व्यवस्था लम्बे समय तक चलने वाली खेती नितियो को अपनाई गई ओर किसानो पर कोई पाबन्दी नही होगी कि वो अपनी उपज दुसरे देशे में भेज सके और सरकार खपत होने वाली उपजो पर ज्यादा से ज्यादा आयात कर लगायेगी। यह गलत होगा कि हम भोजन को वाणिज्य विभाग के साथ जोड़ दे।

इसके साथ ही जैसे जैसे किसान अपनी पैदावार बढ़ाये जाये तो सरकार खाद्यान पैदा करने वाले और उनको खपत करने वाले के बीच बहुत से सम्बन्ध पैदा करे। खाद्य प्रक्रिया के माध्यम से यह जरूरी है कि खेती बाजार यार्डज की गिनती दुगनी करके खाद्यानो की आवक को बढ़ावा दिया जाये ओर इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी प्रतिभागी बनाया जाये। जब शहरी विकास के लिए फडंस का प्रयोजन किया जाये तो शहरो के लिए लाजमी किया जाये कि किसानो के लिए मार्किट बनाई और रिहायसी इलाको में सण्डे मार्किट बनाई जाये। ज्यादा पैदावार जो बिकरी के लिए मार्किट मे जो न पहुंच पाये ये खतरनाक है। जैसे कहा गया है कि जब एक किसान सख्त मेहनत करता है तो अमीर हो जाता है और जब बहुत से किसान सख्त मेहनत करते है तो गरीब हो जाते है।

इस तरह अगर ऋण, सिंचाई ओर सहकारिता पर हमारे सोच और विचारो को लागू किया जाये तो हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते है जिसमे हमारे बच्चे बहुत ज्यादा सुरक्षित होगें और व हमारे पूर्वजो की तरह भूख और गरीबी की दल दल में नहीं रहेंगे। अगर हम ऐसा नही कर पाते तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जायेंगे। जिससे हमने बर्लीन में अर्न्तराष्ट्रीय हरित सप्ताह में पाया जहां यह पूछा गया कि किसान साल के किस महीने में सबसे कम दुःखी होता है तो जवाब मिला फरवरी में। क्योंकि इसमें पहले ही कम दिन होते है। आज फरवरी ही वो महीना है जिसमें वित्तमत्रीं अरूण जेटली ने बजट पेश करना है और हम सांस रोककर उसका इंतजार कर रहे है।

स्वर्ग के लिए लगाातार इंकार

लगभग 700 साल पहले, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दिल्ली पर राज किया, ने कृषि मंत्रालय शुरू किया और वह सारी समतल भूमि को खेती के अन्तर्गत लगाना चाहता था। तुगलक उच्च (ज्यादा) मूल्य वाली फसलों की खेती करना चाहता था। और उसने फैसला सुनायाः ''जहां गेहूँ उगाया जाता है, वहां जौ उगाया जाना चाहिए, और जहां जौ उगाया जाता है वहां गन्ना उगाया जाना चाहिए, और जहां गन्ना उगाया जाता है, वहां खजूर और अंगूर उगाया जाना चाहिए। सदियों तक, परिवारों के खेतो को नष्ट करने में वो विफल रहा। फिर भी, हम इसे कृषि का विविधीकरण कहते है।

अन्नतः अब केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के एकाकी (अकेले) अस्तित्व को खत्म करने का समय आ गया है, प्रभावी रूप से कृषि एक राज्य का विषय है। यहां तक कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और जल संसाधनों का विलय भी हमें उस स्टीक तूफान से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है जो हमने रचा है क्योंकि कृषि नीति को कृषि से बाहर के लोग प्रभावित करते है। जब नीति और कार्यान्वयन (नीति को लागू करना) अतीत की तुलना में अधिक दृढ़ता के साथ तैयार नहीं होता है तो अच्छे इरादे होने पर भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में बढ़ावा होता है। जैसे कि किसानो को मिलने वाली सीधी सब्सिडी ट्रांसफर एक सकारात्मक विकास हो सकता है अगर यह भावी असपष्टता को संबोंधित कर रहे हों। इसी तरह से, अगर ग्रामीण सहकारी बैंको के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात मापदडों को कम नही किया जाता है, तो ऐसे बैकों की दुकान बंद हो जाएगी और गलत कृषि उधार संख्या खाते बढ़ते जाएंगें। यह नीति सिर्फ विचारों को बढ़ावा देने वाली या शानदार घोषणाओं वाली नहीं है, बल्कि यह संसारिक व सावधानीपूर्ण नीति है जो नीरसता व विधिपूर्वक लागू की गई है, जो खुशहाली लाती है।

इस साल, विविधीकरण, प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से राज्य सरकार द्वारा दिए गए रियायती बीज खरीद कर मैने मक्का लगाया। जब मै अपनी उपज बेचने के लिए गया तो केन्द्र सरकार ने वादा किए हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने से मना कर दिया। नीति निर्माता खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए फल व सब्जियों के आयात की वकालत करते है, परन्तु मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का संबंध उत्पादन सीमा के साथ नहीं बल्कि मार्किटिंग खराब करने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ है। खाद्य प्रोसैसिंग (प्रसंस्करण) को बढ़ाने का समाधान उघोगो को कर प्रोत्साहन देने में नहीं, बल्कि खाद्य प्रोसैसिंग उद्योग व अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय में है। कपास एक कृषि उपज है परन्तु नीति और मूल्य कपड़ा मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। वस्तुतः सरकार के सभी स्तरों पर ऐसी विसंगतिया अनन्त हैं। इस तहर की कुंठाओं को सही तरीके से संबोधित करने के लिए और सरकार संचालन सुधारने के लिए और विभिन्न विभागो, केन्द्रीय मत्रांलयों और राज्य सरकारों के बीच कार्यक्रमों के एकीकृत करने के लिए 'राष्ट्रीय' सुरक्षा सलाहाकार' की तरह एक 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार' होना चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर वितरण हो सके।

आंबटन के बाद पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाए ये भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। दुर्लभ संसाधनों को बाढ़ सिंचाई परियोजनाओं को लगाने मे निवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऋण संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार फर्म और व्यवसायिक घराने निहित स्वार्थो के चलते ज्ञान का सबसे अच्छे भण्डार नहीं है। क्योंकि बैंकर्स को प्राथमिकता क्षेत्र उधार दायित्वों को पूरा करने में देना चाहते हैं। उन परामर्श फर्मों पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता जिन्होंने दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को बीच में छोड़ दिया है। यह अधिक बचते और प्रशिक्षण दस्तावेजी असफलताओं से होता है। नतीजतन, कई जगहों पर भूमि पर पानी भराव हो गया है और शेष भारत में भूजल तालिका में कमी हो रही है। मौजूदा सिंचाई के ढांचों की मुरम्मत करना, जल भंडारण टैंक बनाना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन, व सभी किसानों की मिट्टी की नमी मापने वाले उपकरण बांटने पर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, कई गुना फसल प्राप्त कर सकते हैं। देश के किसी अतिरिक्त खर्च के, कई गुना फसल प्राप्त कर सकते हैं। देश के नेतृत्व को लोगों की अपेक्षाओं को लगातार ऊपर उठाने की बजाय पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। नहीं तो व्यवहारिक नीतियों के लिए भी जन समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाएगा।

1957 में हमारी एक संगोष्टी (सैमीनार) में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित खाद्य लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत को केवल अकेले वित्तीय आंबटन पर निर्भर रहते हुए ऐसा नहीं कर सकता बल्कि हम यह लक्ष्य खून और पसीने से हासिल करेंगे। परन्तु उनके कार्यकाल में और भारत की आजादी के पहले 15 सालों में, भारत ने अपना ध्यान खेतों में कृषि क्रान्ति पर केन्द्रित करने की बजाए बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण को प्राथमिकता दी। कई दश्कों से सोवियत संध की 'पचं वर्षीय योजना' पर आधारित विकास ने हमारा सिर ऊचा रखने में हमारी मदद की है। हमने बहुत समय दूसरों की काफी नकल कर ली है, आओ समझे कि हमारी समस्याएं अद्वितीय हैं और इसलिए इसके समाधान भी अलग होने चाहिए।

हमारे खून पसीने का फल लेने के लिए, हमें प्रयोग किए गए और प्रक्रिया के बीज बीजने चाहिए। भारत को कृषि अनुंसधान व विकास पर खर्च बढ़ाकर इस क्षेत्र का कुल घरेलू उत्पाद का 1 कर देना चाहिए। केवल वित्तीय आबंटन ही मदद नहीं करेंगा। अब गेंहूं को फूस (तूड़ी) से अलग करने का समय आ गया है, कृषि अनुसंधान को कृषि सलाहकार सेवाओं से अलग करने की जरूरत है। अनुसंधान पर बहुत अधिक ध्यान और दोनो मोर्चो पर डिलीवरी की कमी से भारत के विकास प्रक्षेपवक्र (ट्रैजेक्टरी) को भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम की भविष्य अनिश्चितताओं और अस्थिर कमोडिटी कीमतो का सामना करने के लिए व जोखिम नवीनीकरण के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है। नीति आयोग को, अपने नए अवतार में, नीति बनामें में कुछ ज्यादा चुस्त होने की जरूरत है नही तो हम अपनी क्षमता को पहचानने में असफल होंगे और हम एक विकासशील देश ही रहेंगे जैसा कि सैमुअल बैकट के इन शब्दों में व्यक्त किया गया है कि ''हमारी जिदंगी स्वर्ग के लिए लगातार किए गए इंकार का एक क्रमिक है''।